# स्लम सांख्यिकी/जनगणना पर समिति का प्रतिवेदन

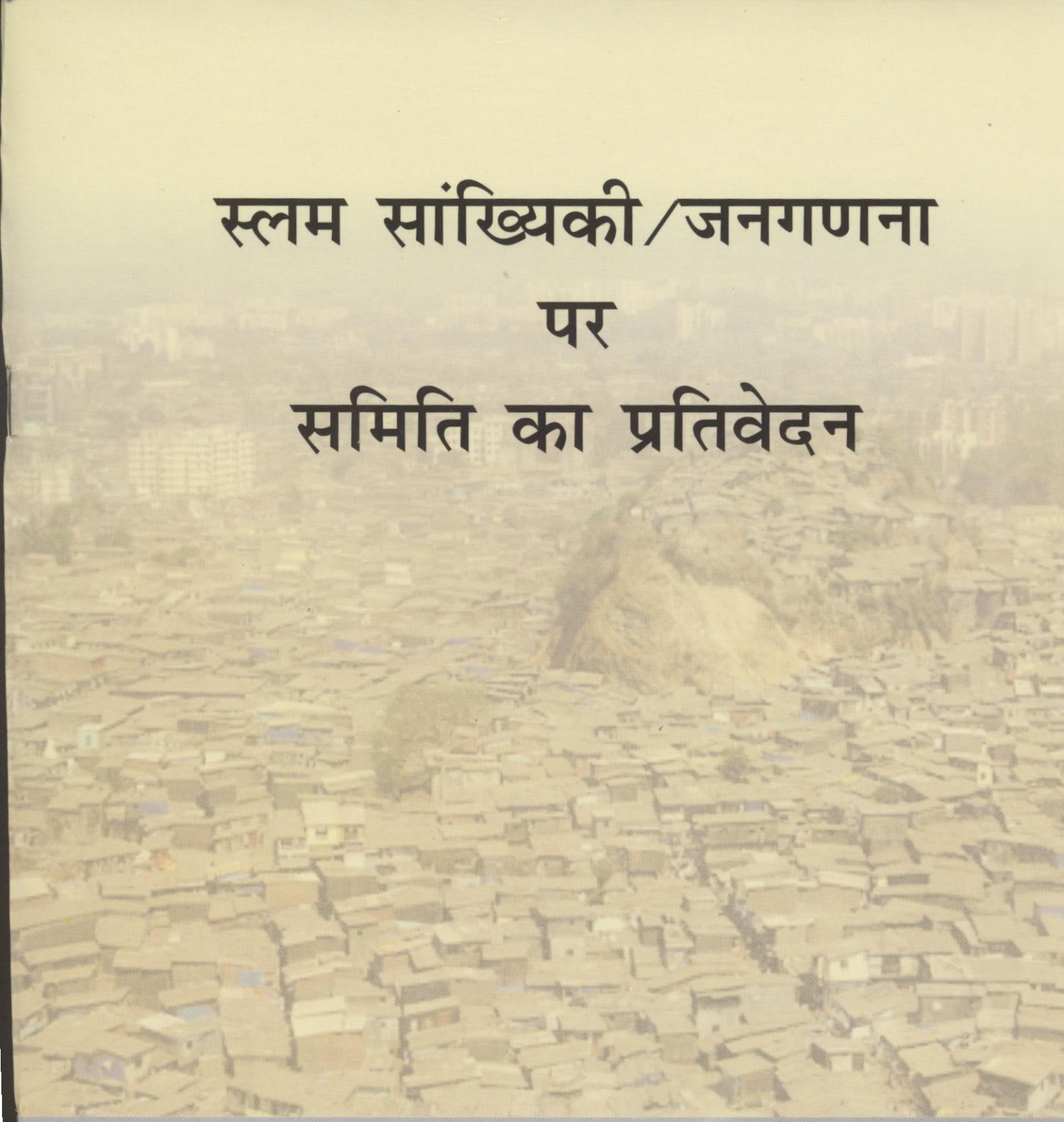

सत्यमेव जयते

**भारत सरकार**

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

# स्लम सांख्यिकी/जनगणना
# पर
# समिति का प्रतिवेदन

भारत सरकार
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन
नई दिल्ली

कुमारी शैलजा
माननीय मंत्री आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

**विषय** **स्लम संगणना के संचालन से सम्बन्धित मुद्दों एवं स्लम सांख्यकी/संगणना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु समिति की रिपोर्ट**

महोदया,

कार्यालयज्ञापन दिनांक 4 जुलाई 2008, एनबीओ, एचयूपीए मंत्रालय द्वारा गठित स्लम संगणना के संचालन से सम्बन्धित मुद्दों एवं स्लम सांख्यकी/संगणना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हम अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं।

भवदीय,

डा. प्रणव सेन
(अध्यक्ष)

सदस्य
(डा. पी.के. मोहंती)
अपर सचिव (ज.ने.रा.न.मि.)
एचयूपीए मंत्रालय

(जे.दाश)
महानिदेशक, एन.एस.एस.ओ.
सांख्यकी एवं का.का. मंत्रालय
भारत सरकार

(डा. सी. चन्द्रमौली)
रजिस्ट्रार निदेशक
और भारतीय संगणना आयुक्त

(एल.पी. सोनकर)
वरिष्ठ सलाहकार
योजना आयोग

(गिरीश शोनकर)
सचिव (शहरी विकास एवं
आवास), बिहार सरकार

(पुष्पा सुब्रह्मणयम)
प्रधान सचिव, निगम प्रशासन,
आन्ध्र प्रदेश सरकार

(एस.आर. कुंटे)
सचिव (आवास)
महाराष्ट्र सरकार

(के. सुरेश)
प्रधान सचिव
योजना एवं सांख्यकी
मध्य प्रदेश सरकार

(नवनीत सहगल)
सचिव (यूई एवं पीए) श.रो. एवं ग.उ.
उत्तर प्रदेश सरकार

(डी.एस. नेगी)
निदेशक (एनबीओ) एवं वि.का.अ.
ज.ने.रा.न.मि. एवं रा.आ.यो.
अ.श.ग.उ मंत्रालय

डॉ. प्रणव सेन
**DR. PRONAB SEN**
प्रधान सलाहकार
PRINCIPAL ADVISER

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
योजना आयोग
योजना भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली–११० ००१
Government of India
Planning Commission
Yojana Bhavan, Parliament Street
New Delhi-110 001
Telefax : 23096579
E-mail : pronab@nic.in

# प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र की सहस्त्राब्दी उद्घोषणा के अनुसार, जिसका भारत भी एक हस्ताक्षरी है, स्लमवासियों के जीवन को सुधारने की आवश्यकता को विशेषरूप से मान्यता दी गई है। स्लमों का अस्तित्व एवं उनका तीव्र फैलाव खासतौर पर विकासशील देशों में तेज है क्योंकि शहरीकरण की गति तेज हो रही है तथा भारत भी इसका अपवाद नही है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए तथा वैश्विक समुदाय एवं हमारे अपने लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए, भारत सरकार ने स्लमवासियों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। हालांकि यह पाया गया कि आंकड़ों की कमी के कारण इस कार्यक्रम की रूपरेखा अत्यधिक बाधित हुई। आंकड़े न केवल भारतीय स्लमों के जीवन की परिस्थितियों से सम्बन्धित है बल्कि वस्तुत: स्लम की जनसंख्या के आकार एवं विस्तार से भी सम्बन्धित है। इसके परिणामस्वरूप आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा स्लम आकड़ों/जनगणना पर मेरी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिससे स्लम आकड़ों/जनगणना के विभिन्न पहलुओं तथा स्लम जनगणना 2011 के संचालन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके।

समिति ने पाँच बैठकें आयोजित की जिसमें से एक खास बैठक आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा आयोजित की गई। यह रिपोर्ट इन चर्चाओं तथा उन अध्य्यनों का परिणाम थी जो हमारे ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए किए गए थे। यह दावा नही किया जा सकता कि यह रिपोर्ट किसी भी रूप में इस विषय पर अंतिम प्रस्तुति है। बड़े और तेजी से बढ़ते हुए शहरों में जैसे भारत में शहरीकरण एवं स्थानांतरण की गति को आसानी से पकड़ पाना जटिल है।

समिति ने भारतीय कृषि सांख्यकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.) जो देश का प्रमुख सांख्यकी अनुसंधान संस्थान है, को नवीनतम सांख्यकी तकनीक का प्रयोग करते हुए एक आंकलन प्रक्रिया चलाने के लिए स्थापित किया है, जिससे सूचनाओं की उन कमियों को दूर किया जा सके जो वर्तमान में मौजूद हैं। हम आई.ए.एस.आर.आई एवं रा.भ.नि.स. की टीम के अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने अल्पसूचना के आधार पर इस प्रक्रिया को हाथ में लिया एवं सराहनीय कार्य किया।

डॉ. सी.चद्रमौली, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त तथा उनकी टीम के समर्पित अधिकारियों ने अपने पद की जिम्मेदारियों से परे जाकर इस रिपोर्ट में अपना योगदान दिया। हम उनके अत्यंत आभारी है कि उन्होंने छोटे स्लम समूहों की पहचान करने के लिए प्रयोगात्मक अध्ययन किया तथा समिति